

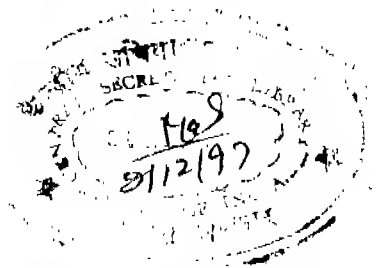


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 573 ]  
No. 573]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 7, 1997/आश्विन 15, 1919  
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 1997/ASVINA 15, 1919

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1997

आय-कर

का.आ. 713 ( अ ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 15) द्वारा यथासंशोधित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80एक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 1997 है ।  
(ii) ये 1 अक्टूबर, 1994 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 में, भाग 2 के उपभाग ड में,—
  - (i) नियम 11डक को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप नियम (1) में, प्रारम्भिक भाग में, "औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए" शब्दों के स्थान पर "प्रवर्ग 'क'—औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को विनिर्दिष्ट करने के लिए" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे,
  - (ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) धारा 80 डक की उपधारा (2) के खण्ड (iv) के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी जिले को प्रवर्ग "ख" के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करते समय केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान करेगी कि,—

(क) उपनियम (1) के खण्ड (क) में वर्णित "अखिल भारतीय श्रेणीक्रम सूची" में जिले का "कुल भारत सूचकांक", 250 से अधिक है किन्तु 500 से कम है या उसके बराबर है :—

परन्तु ऐसे किसी जिले को इस उपनियम के अधीन अधिसूचित नहीं किया जाएगा यदि उक्त जिला उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है।”

### स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-इक के प्रयोजनार्थ औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन समूह गठित किया था। उक्त समूह ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 1994 के अक्टूबर मास में प्रस्तुत कर दी थी। केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट के पुनरीक्षण के लिए एक अन्य अध्ययन समूह गठित किया था। उक्त दोनों अध्ययन समूहों की रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने यह विनिश्चित किया है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को दो प्रवर्गों अर्थात् प्रवर्ग “क” और प्रवर्ग “ख” में वर्गीकृत किया जाए। आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 15) द्वारा धारा 80-इक का ऐसा संशोधन किया गया था जिससे कि प्रवर्ग “क” औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले और प्रवर्ग “ख” के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में उन्हें वर्गीकृत किया जा सके। उक्त अध्यादेश 16 सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त हो गया था। आय-कर नियम, 1962 का नियम 11-इक तारीख 1-10-1994 से सूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है जिससे कि उक्त अध्यादेश द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 80-इक में किये गए संशोधन को प्रभावी किया जाए। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संशोधन के भूतलक्षी प्रवर्तन से निधीरहितों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[संख्या 104/अ.सं. 142/20/94-टी.पी.एल.]

डॉ. धीरज भटनागर, अवसर सचिव

**पाद टिप्पण :**—मूल नियम अधिसूचना का. आ. संख्या 969 (अ) तम्र 26-3-1962 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें अन्तिम संशोधन का.आ. सं. 649(अ) तारीख 10-9-97 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किये गये थे।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

## CENTRAL BOARD OF DIRECT-TAXES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1997

### INCOME-TAX

**S.O. 713(E).**—In exercise of powers conferred by section 80IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) as amended by section 3 of the Income-tax (Amendment) Ordinance, 1997 (15 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (i) These rules may be called the Income-tax (Eleventh Amendment) Rules, 1997.
- (ii) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of October, 1994.
2. In the Income tax Rules, 1962, in Part II, in sub-part E,—
  - (i) rule 11EA shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and in sub-rule (1) as so renumbered, in the opening portion after the words, "in specifying a district for notification as an industrially backward district", the words and letter "of Category 'A'" shall be inserted;
  - (ii) after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—
    - "(2) In specifying a district for notification as an industrially backward district of Category 'B' under sub-clause (c) of clause (iv) of sub-section (2) of section 80IA, the Central Government shall satisfy itself that,—
    - (a) the district has a "Total Weighted Index Count" of more than 250 but less than or equal to 500 in the 'All India Gradation List' as indicated in the 'All India Gradation List' mentioned in clause (a) of sub-rule (1) :  
Provided that no district shall be notified under this sub-rule if such district has been notified under sub-rule (1)."

### Explanatory Memorandum

The Central Government had set up a Study Group to identify industrially backward districts for the purposes of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961. The Group submitted its Report to the Central Government in the month of October, 1994.

The Central Government constituted another Study Group to review the said Report. On the basis of the reports of both the Study Groups, the Central Government decided that the industrially backward districts should be classified in to two categories i.e., Category 'A' and Category 'B'. Section 80-IA was amended by the Income-tax (Amendment) Ordinance, 1997 (15 of 1997) so as to classify the industrially backward districts of category 'A' and industrially backward districts of category 'B'. The said Ordinance has come into force on the 16th September, 1997. Rule 11EA of the Income-tax Rules, 1962 is being amended retrospectively with effect from 1-10-1994 so as to give effect to the amendment made in section 80-IA of the Income-tax Act by the said Ordinance. It is certified that the retrospective operation of this amendment shall not prejudicially affect the interest of assesseees.

[No. 10440/F. No. 142/20/94-TPL]

DR. DHEERAJ BHATNAGAR, Under Secy.

**Foot Note :** The Principal rules were published vide Notification being S.O. No. 969 dated 26-3-1962 and last amended by Notification published under S.O. No. 649(E) dated 10-9-1997.

